[श्री राजीव सातव]

जो decision आया है, उसमें यह आरक्षण खतरे में आया है - ऐसी स्थिति सबके सामने है। इसलिए आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय की larger Bench के सामने यह मामला hearing के लिए है। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो hearing हुई थी, उसमें केन्द्र सरकार ने अपनी बात नहीं रखी थी। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि आने वाली larger Bench की hearing में राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार भी मराठा आरक्षण के पक्ष में बात रखे, ताकि मराठा आरक्षण कायम रहे, धन्यवाद।

SHRI SHARAD PAWAR (Maharashtra): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Rajeev ji, please take note that you have already come to the Rajya Sabha and then you are in the upper gallery. You are still remembering the Speaker. You have to say 'Chairman' here.

Revival of National Paper Industries in Assam and release of pending salaries/statutory dues to workers/employees

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a very important issue pertaining to the economy of Assam.

There are two paper mills which are public sector undertakings. One is in Nagaon and the other one is in Panchgram. These two are the only public sector undertakings earning profit in Assam. But suddenly what happened is that both the paper mills have been facing loss since 2014 and ultimately from 2016 onwards it is being closed down. From 2016 to till date, the State Government as well as the Central Government have been giving assurances to give special package for revival of these two paper mills. But nothing has been done till today. You will be surprised to know this. In the meanwhile, the employees have not been getting salary for four years. Seventy workers have died so far for want of salary and medicine and three employees have committed

suicide. Apart from that, there are two lakh employees who are either directly or indirectly engaged with these paper mills. But now their future is finished. On the other hand, bamboo farmers, who are dependent on these two paper mills, and bamboo cultivation have also been finished.

Now, due to the outbreak of COVID-19, thousands and thousands of young boys have moved out of Assam because they have lost their jobs. So, this paper mill should be revived. My request to the Government is to revive this paper mill immediately as per the assurance of the Government so that economy can be restored. Thank you.

SHRIMATI ARPITA GHOSH (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RANEE NARAH (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Concern over suicides by labourers who lost their jobs during the lockdown

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, आपने अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आपकी कृपा इसी तरह से बनी रहेगी। श्रीमन बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात कहूंगा। लॉकडाउन के कारण देश में छोटे-बड़े कारखानों के बंद होने से, कारोबारियों का कारोबार बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके परिवार बिखर गए हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तो दूर, उन्हें कभी-कभी भूखे पेट सोने के लिए विवश होना पड़ रहा है। पढ़े-लिखे लोगों के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, उनको पांच साल के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर रखा जा रहा है और पांच साल के बाद समीक्षा की जाएगी। वे भी असमंजस में हैं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नतीजा यह है कि लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर लोग हताशा की स्थिति में जी रहे हैं। नतीजा यह है कि वे आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इन चार-पांच महीनों में कोविड की वजह से अकेले नोएडा में 44 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन कल तक 165 लोगों ने वहां पर आत्महत्या की है। वहां की यह स्थिति है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से नौकरियों से, मजदूरी से अलग हो गए हैं, उनको प्रतिमाह कम से कम 15,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएं ताकि वे कम से कम भूखों न मरें और वे जिंदा बने रह सकें। लोकतंत्र में पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर गवर्नमेंट यह कर रही है, हमें भी यह करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और रोज़ाना देश में जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए एक सार्थक कदम उठाएं।